भारतीय मजदूर संघ

महामन्त्री का प्रतिवेदन

17/11/86

पंचम् अखिल भारतीय अधिवेशन

जयपुर

दि० २१, २२ व २३ अप्रैल, १९७८

भारतीय मजदूर संघ

महामन्त्री का प्रतिवेदन

दि० २१, २२ व २३ अप्रैल, १९७८ को जयपुर में हो रहे पांचवें अखिल भारतीय अधिवेशन में प्रस्तुत

आदरणीय अध्यक्ष श्री दत्तोपंत जी ठेंगडी तथा प्रिय प्रतिनिधि बन्धुओं,

अमृतसर के अप्रैल, 77 के अपने अ० भा० अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्र को विशेषकर मजदूरों को तानाशाही के घुमड़ते हुए खतरे की ओर सजग किया था। दुर्भाग्यवश यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुयी। आपातस्थिति में भारतीय मजदूर संघ की इकाइयों व यूनियनों ने बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। ऐसे संकट के दिनों में भी अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां जारी रखी तथा जहां उन्होंने हड़ताल व आन्दोलन करना उचित समझा, बिना किसी हिचकिचाहट के आन्दोलन व हड़तालें भी की। आपात स्थिति के विरुद्ध चलाये गये 'लोक संघर्ष' में भारतीय मजदूर संघ के 1 लाख से भी ऊपर कार्यकर्ताओं ने कानून को तोड़ा तथा 5 हजार कार्यकर्त्ता जेलों में बन्द हुये। इनमें 250 मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध थे। भारतीय मजदूर संघ ने आपातस्थिति के विरोधी अन्य श्रमिक संगठनों को भी एक मंच पर जुटाने का सफल प्रयास किया तथा इन्दिरा तानाशाही के अन्तर्गत चल रही श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त रुप से विरोध आयोजित किया। भारतीय मजदूर संघ ने इमरजेन्सी के विरुद्ध मजदूरों में जागृति लाने के लिए अनेक प्रकार के पत्रक व पुस्तिकायें जैसे "Searchlight on Labour" तथा "आपातस्थिति में पिसता हुआ मजदूर" प्रकाशित करके स्वतंत्रता की मशाल जलाये रखा।

वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव के पूर्व भारतीय मजदूर संघ ने अन्य

श्रम संगठनों की मदद से "जनतांत्रिक मजदूर मंच" की स्थापना करके सभी राष्ट्रवादी व जनतंत्रीय तत्वों को एक मंच पर लाकर जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों को पूरा समर्थन दिया, क्योंकि उस समय के सत्तारूढ़ दल के सामने जनतापार्टी ही एकमेव ऐसी विकल्प थी।

तानाशाही के उध्वस्त होने और प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के बाद भारतीय मजदूर संघ ने चुनाव जैसे राजनीति को जो आपत् धर्म के नाते राष्ट्रनीति के अंग के रुप में स्वीकार किया था, उसे छोड़कर अपने मूल कार्य जो वास्तविक व सही (जेन्यूइन) ट्रेड यूनियन आन्दोलन है, उसे फिर से करना आरम्भ कर दिया।

अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति लगन व निष्ठा के कारण भारतीय मजदूर संघ ने समूचे देश में उल्लेखनीय कार्य का व्याप बढ़ाया है। और अब आपातस्थिति के पश्चात् जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उनको स्थायी बनाने का कार्य अपने कन्धों पर आया है, साथही नये नये कार्यकर्ताओं को पुराने कार्यकर्ताओं को समान स्तर पर लाने की भी जिम्मेवारी आयी हुयी है। इस प्रकार संख्यात्मक और गुणात्मक कार्य बढ़ाने का दायित्व अपने ऊपर है।

श्रद्धांजलि

अत्यन्त दुख की बात है कि इस अवधि में भारतीय मजदूर संघ ने अपने कई नेताओं व प्रमुख कार्यकर्ताओं को खो दिया है। ये सभी सक्रिय व कार्यशील अवस्था में ही हमसे बिदा हो गये हैं।

हम अपने भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विनय कुमार मुखर्जी के पितृवत् नेतृत्व से वंचित हो चुके हैं। ये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे और भारत के ट्रेड यूनियन आन्दोलन को इनका अमूल्य योगदान था। भारतीय मजदूर संघ की रचना में इनका बड़ा भारी सहयोग था। इनके निधन से अपूरणीय क्षति हुयी है। इनके समर्पित जीवन से सभी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को भविष्य में भी प्रेरणा मिलती रहेगी।

मृत्यु ने हमारे और कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को भी छीना है। (1) आसाम प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री अखिलरंजनदास गुप्त (2) अखिल भारतीय इन्जीनियरिंग मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री

रघुनाथ सहाय जैन (गाजियाबाद) (3) अखिल भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री हंसदेव सिंह गौतम (कानपुर) (4) चित-रंजन रेल इन्जन कारखाना कर्मचारी संघ के महामन्त्री श्री नृपेन्द्रनाथ घोष (5) मावड़ (महाराष्ट्र) तहसील के मजदूर संघ नेता श्री वाला साहेब जाधव (6) पूना भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय मन्त्री श्री काका महाजनी (7) सौराष्ट्र भारतीय मजदूर संघ के नेता श्री दोस्त मुहम्मद (राजकोट) (8) पिन्चवैली कोल माइन्स के मजदूर संघ नेता श्री मुखलाल तथा (9) श्रीगंगानगर (राजस्थान) के मजदूर संघ के प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता श्री ज्वाला सिंह जैसे कार्यकर्ताओं को खोकर भारतीय मजदूर संघ का परिवार आज दुखित है।

भारत माता के इन लाड़ले सपूतों की पावन स्मृति को हम संजोकर रखेंगे तथा इन्हें अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं।

कार्य की प्रगति

विगत अमृतसर अधिवेशन के पश्चात् भारतीय मजदूर संघ का कार्य सभी प्रदेशों व उद्योगों में द्रुतगति से बढ़ रहा है।

वर्ष 1974 के अन्त में जहां भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्धित यूनियनें 1313 थी, वहीं 1977 के अन्त में 1555 हो गयीं है तथा वर्ष 1974 में सदस्य संख्या जहां 839, 423 थीं, वहीं 1977 के अन्त में 10,83, 488 हो चुकी है।

इस बीच दिसम्बर 8 अक्तूबर, 1977 को कान्फेडरेशन आफ सेन्ट्रल एन्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज, नामक सहयोगी संस्था की भी स्थापना हुई, जिसकी सदस्य संख्या अब तक 11 लाख तक पहुंच चुकी है।

भा० मजदूर संघ से सम्बद्ध वर्तमान समय में कुल 17 औद्योगिक महासंघ सक्रिय रुप से कार्यरत हैं तथा इस अधिवेशन में निम्नलिखित उद्योगों के महासंघ बनने जा रहे हैं।

(1) बीड़ी उद्योग

(2) बुनकर

(3) भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०

(4) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया

(5) डेरी

(6) ओ० एन० जी० सी०

(7) इ० डी० स्टाफ (पोस्टल)

(परिशिष्ट 1 पर वर्ष 1977 के अन्त तक की सम्बद्ध यूनियनों व सदस्य संख्या प्रदेशों के अनुसार संलग्न है तथा परिशिष्ट 2 में औद्योगिक महासघों की सदस्यता अंकित है।)

प्रतिनिधित्व

इस अवधि में भारतीय मजदूर संघ को विभिन्न समितियों व गोष्ठियों तथा परिसम्वादों में प्रतिनिधित्व मिला है।

(जिसका विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

संघर्ष तथा उपलब्धियां

इस अवधि में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें पर्याप्त रूप से सक्रिय रहीं हैं तथा अनेक उपलब्धियां व सफलतायें प्राप्त की हैं, जिनमें से कुछ के विवरण यहां दिये जा रहे हैं :

डी० डी० ए०, मदर डेरी, दिल्ली मिल्क स्कीम, दिल्ली परिवहन, दिल्ली राज्य प्राइवेट, स्कूल्स प्यूरोलेटर, आनन्द आटो तथा होटल आदि संस्थानों में यूनियनों ने आन्दोलनों के माध्यम से मांगे पूरी कराई हैं। किशनगंज के इन्जीनियरिंग व कपड़ा मिलों में बोनस दिलाने में सफलता मिली है।

चांदनी चौक के कपड़ा मण्डी के कर्मचारियों को 40 रुपये वेतन बढ़ोत्तरी तथा महगाई बढ़ने के कारण एक मांस का अतिरिक्त वेतन दिलाने से सफलता मिली है।

बदरपुर थर्मल पावर में हड़ताल के फलस्वरूप मांगे पूरी हुयी है।

डेसू के कर्मचारियों ने आन्दोलनों व प्रदर्शनों के माध्यम से मांगे पूरी करायी हैं।

धारीवाल ऊलेन मिल में 25 दिनों की हड़ताल कराकर मांगे पूरी करायी गयी हैं।

घी मिल्स राजपुरा में 4 दिन की हड़ताल के फलस्वरूप मजदूरों के वेतन में 13 रुपये प्रतिमास की बढ़ोत्तरी तथा 20 प्रतिशत बोनस प्राप्त हुआ है।

एक दिन हड़ताल के फलस्वरूप बिस्कुट फैक्ट्री राजपुरा में 14 प्रतिशत बोनस मिला है।

हिन्दू वायर फैक्ट्री, पटियाला में आन्दोलनों के माध्यम से 15 कर्मचारियों को काम पर वापस रखाया गया तथा 20 प्रतिशत बोनस की भी मांग पूरी करायी गयी।

मिलटरी डेरी फार्म इम्पालइज यूनियन ने 23 अगस्त, 1977 से प्रतिरक्षा मन्त्री के निवास पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करके कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं उत्पीड़न रुकवाने में सफलता पायी है।

नवयुग रबर इन्डस्ट्री जालन्धर में दो मास के आन्दोलन के फलस्रूप बोनस व वेतन वृद्धि की मांग पूरी हुयी है।

प्रिन्टिग प्रेसेस बटाला में 10 प्रतिशत की वेतन वृद्धि करायी गयी है।

ओसवाल ऊलेन मिल्स में 13 प्रतिशत बोनस दिलाया है।

म्युनिसिपल कारपोरेशन लुधियाना में आन्दोलनों के फलवस्रूप डेली वेजेज मजदूरों को 3 वर्षों व 5 वर्षों की सेवा के उपरान्त नियमित व स्थायीकरण कराने में सफलता मिली है।

म्युनिसिपल कमेटी अबोहर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी दिलाने में सफलता मिली है।

पठानकोट के 45 कर्मचारियों का विक्टीमाइजेशन रद्द कराने में सफलता मिली है।

मीटर इन्स्ट्रूमेन्ट्स कारखाना चण्डीगढ़ में 3 सप्ताह के संघर्ष के पश्चात् मजदूरों ने बोनस प्राप्त किया।

चण्डीगढ़ स्थित पंजाब पब्लिक सेक्टर के एक फाइनेन्सियल कारपोरेशन में कर्मचारियों को दो बढ़ोत्तरी दिलवाकर प्रत्येक कर्मचारी को 30 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिमास की वृद्धि कराई। इसी संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को 20 प्रतिशत बोनस दिलाने में सफलता मिली है।

सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद एवं जगाधारी में अपनी यूनियनों ने संघर्ष करके तथा न्यायालयों के माध्यम से भी कर्मचारियों को काम पर वापस कराये हैं तथा वेतन वृद्धि व बोनस की मांग पूरी करायी है।

उत्तर प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी परिषद ने विधान सभा के सम्मुख सात दिन की भूख हड़ताल रखी जिसमें 650 कर्मचारी सम्मिलित हुये और सेवा नियम बनवाने में सफलता प्राप्त की।

डोईवाला सुगर फैक्ट्री में 24 कर्मचारियों को काम पर वापस दिलाने में यूनियन को सफलता मिली।

हरिद्वार स्थित एन्सीलरी कर्मचारियों के लिये सेवा नियम बनवाने में सफलता मिली।

ओ० एन० जी० सी० देहरादून के कर्मचारियों को भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से 22.50 प्रतिशत बोनस मिला।

हिमालय ड्रग्स देहरादून के कर्मचारियों को 35 रुपये प्रति मास वेतन में बढ़ोत्तरी कराई गयी।

देहरादून के सिलाई उद्योग (दर्जी) में लगे कर्मचारियों के वेतन में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि करायी गयी।

वाराणसी स्थित साहू केमिकल्स के 158 ठेके के कर्मचारियों को नियमित कराया गया।

वाराणसी के 'आज' समाचार पत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 45 रुपये की अन्तरिम राहत दिलाई गयी।

वाराणसी के कनौड़िया फ्लोर मिल में 10 रुपये से 38 रुपये, स्वस्तिक फार्मास्युटिकल्स में 15 रुपये से 40 रुपये तथा नेशनल वाइण्डर के कर्मचारियों को 10 रुपये से 20 रुपये मासिक की वेतन में वृद्धि करायी गयी। टुल्स इलेक्ट्रीकल्स में 20 रुपये की अन्तरिम सहायता प्राप्त हुयी।

इलाहाबाद स्थित जयश्री टायर के कर्मचारियों को 50 रुपये वेतन वृद्धि कराने में यूनियन सफल हुई।

बी० एच० इ० एल० ओबरा के कर्मचारियों को 30 रुपये वेतन वृद्धि एवं आवास व्यवस्था करायी गयी।

कानपुर के यू० पी० लैमिनेटर्स के कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप वेतन में 20 रुपये से लेकर 65 रुपये तक वृद्धि हुयी।

उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के प्रयास से रिवर साइड पावर हाऊस कानपुर के 4000 मजदूरों को वर्दी मिली।

लखनऊ स्थित यू० पी० एस्बेस्ट्स के कर्मचारियों को 50 रुपये की अन्तरिम सहायता दिलायी गयी।

बरेली तराई विकास निगम के कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली के बनाई गयी।

बिहार प्रदेश विद्युत : श्रमिक संघ धरना, अनशन आदि के द्वारा 28 जून, 1977 को प्रबन्धक को प्रथम बार द्विपक्षीय समझौता के द्वारा 20 रुपये प्रतिमाह की दर से अन्तरिम सहायता तथा 300 कनीय लेखा, लिपिकों (एप्रेन्टिसों) की सेवा नियमित कराने में सफल हुआ। साथ ही पतारनू थर्मल में 8 दिनों के लगातार धरने के फलस्वरूप विद्यालय, चिकित्सा सुविधा तथा अनियमितों की नियमित सेवा करायी गई।

हैवी इन्जीनियरिंग, रांची में हटिया श्रमिक संघ के द्वारा 19 अगस्त, 1977 को 8 दिनों के लगातार धरने के फलस्वरूप एच० एम० वी० पी० के 107 कर्मचारियों को इन्सेन्टीव दिलाया गया। इसके अतिरिक्त 8 दिनों की हड़ताल होने पर एच० एम० टी० पी० के

मजदूरों की गलत सेवा शर्तें समाप्त करायी गयीं। साथ ही 10 मृतक मजदूरों के परिवार को नौकरी दिलायी गई।

बरौनी आयल रिफाइनरी में दो दिनों की पूर्ण हड़ताल कराने पर अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि की मांगें पूर्ण हुई।

टेल्को जमशेदपुर में हड़ताल, धरना घेराव आदि के द्वारा 75 ठेकेदार मजदूरों को नियमित किया गया। तथा 13 मार्च से 19 मार्च 1978 को 5 हजार ठेकेदार मजदूरों ने पूर्ण हड़ताल किया। फलस्वरूप प्रबन्धक ने 70 रुपया प्रति मास तदर्थ वेतन दिया।

ट्यूब कारखाना टाटा नगर में दो दिनों की हड़ताल, घेराव एवं अन्य आन्दोलनों के द्वारा 5 हजार कर्मचारियों को बोनस के रूप में 800 रुपये प्रति कर्मचारी को मिला। साथ ही 300 कैन्टीन ठेकेदार कर्मचारियों को कम्पनी का स्थायी कर्मचारी बनाया गया।

डालमियानगर में 2 से 5 दिसम्बर, 1977 तक घेराव के द्वारा 10 हजार कर्मचारी जो बोनस से वंचित हो रहे थे—उन्हें बोनस मिला।

बिहार शरीफ के 8 दिनों के हड़ताल के फलस्वरूप 25 कोल्ड स्टोरेज के मजदूरों को 10 से 25 रुपये तक वेतन वृद्धि हुई।

कान्द्रा ग्लास वर्क्स में 8.33 प्रतिशत बोनस के अलावा भी 75 रुपये अतिरिक्त अनुदान दिलाया गया।

जयश्री टेक्सटाइल्स (बिड़ला ग्रुप) रिसरा में 400 छटनी शुदा कर्मचारियों को काम पर वापस कराने में यूनियन ने सफलता पायी।

बंगाल की जूट मिलों में बढ़े हुये वर्कलोड, छटनी तथा आपतस्थिति में निकाले गये कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हड़ताल, धरना, प्रदर्शन व अन्य प्रकार के आन्दोलन लिये गये हैं। अन्य बहुत सी समस्याओं में सफलतायें भी मिली हैं।

23 फरवरी, 1978 को आटो इन्डिया राउरकेला में अपनी यूनियन ने समझौता कराकर मजदूरों के वेतन में 90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक

मासिक वृद्धि कराई है ।

दुमदुमा क्षेत्र के चाय बागानों में न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस दिलाने में यूनियन सफल हुई है ।

दिनांक 24 अक्टूबर से दिनांक 9 नवम्बर, 1977 तक घाडगे पाटिल ट्रांन्सपोर्ट में हड़ताल कराकर यूनियन ने मजदूरों के वेतन में 85 रुपये मासिक की वृद्धि दिलाई है ।

कानून के अभाव में भी काम से निवृत्ति पाने वाले घरेलू कामगारों को एक वर्ष काम के पीछे एक मास के वेतन को गैच्युटी के रूप में दिलवाने में सफल हुआ है ।

बाम्बे फिल्म लेबोरेटरी में 20 प्रतिशत, सरदार इलेक्ट्रिकल्स में 20 प्रतिशत, एक्सेल इन्डस्ट्रीज में 20 प्रतिशत, इन्डियन कार्क में 16.50 प्रतिशत तथा लायन पेन्सिल में 16 प्रतिशत बोनस दिलाने में यूनियनों ने सफलता पायी है । फिल्म पेन्टर में हड़ताल की स्थिति ला देने पर मजदूरों ने 20 प्रतिशत बोनस प्राप्त किया है । जे० जे० व्हक्यूम फ्लास्क में 23 प्रतिशत, पंचम इन्डस्ट्रीज पूना में 20 प्रतिशत तथा डेक्कन पोल्ट्री में 12 प्रतिशत बोनस दिलाने में सफल हुये ।

आरिस्टो फार्मास्युटिकल में हड़ताल के फलस्वरूप वेतन में 65 रुपये से लेकर 125 रुपये मासिक की वृद्धि हुयी है ।

सिमैक ग्रुप में समझौते के फलस्वरूप 140 रुपये मासिक वेतन में बढ़ोत्तरी हुई है ।

आयुर्वेद सेवा संघ कारखाने में प्रति कर्मचारी 35 रुपये से 75 रुपये तक मासिक वेतन में बढ़ोत्तरी कराने में सफलता मिली ।

आई० पी० सी० एल० में वरिष्ठिता पर 75 प्रतिशत प्रमोशन कराने के निर्णय में यूनियन ने सफलता पायी है ।

राज्य परिवहन में यूनियन ने वेतन आयोग लागू कराने में सफलता पायी है ।

अगस्त, 1977 में हड़ताल कराकर यूनियन ने टाटा एक्सपोर्ट देवास में ग्रेडेशन की मांग पूरी करायी है तथा मान्यता भी प्राप्त की है।

नवम्बर 1977 में यूनियन ने आन्दोलन का सहारा लेकर भोपाल पुट्ठा मिल में बोनस बढ़वाया है।

भिलाई एच० ए० सी० एल० के कर्मचारियों के आन्दोलन के फलस्वरूप प्रमोशन पालिसी, केटेगराइजेशन व वेतन तथा मंहगाई भत्ते आदि मांगें पूरी हुयी।

अमरावती नगर परिषद कर्मचारी संघ ने औद्योगिक न्यायालयों द्वारा 35 हजार रुपये का एवार्ड कराकर मजदूरों के वेतन में वृद्धि करायी।

बुलढाणा जिला सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने वेतन पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर न्यायालय द्वारा 3 लाख का एवार्ड जीता।

पजाबराव कृषि विद्यापीठ के कृषि मजदूरों को वेतन में प्रतिदिन 1.50 पैसे की वृद्धि कराने में सफलता मिली।

जनवरी, 1978 में अपनी यूनियन ने केरल ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन में एक दिन की हड़ताल कराकर वेतन में 30 रुपये मासिक वेतन बढ़ोत्तरी कराने में सफलता पायी है।

हैदराबाद, सिकन्दराबाद में होटल मजदूरों ने आपातस्थिति में भी हड़ताल आदि करके अपनी मांगे पूरी करायी।

नेलोर के दुकान कर्मचारियों ने आवास के लिये स्थान हेतु आन्दोलन किये।

19 जिलो से सम्बन्धित कर्नाटक एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन में 3 दिनों की हड़ताल के पश्चात 686 ठेके के कर्मचारियों को नियमित कराने में सफलता मिली है।

बंगलोर स्थित सुपर बाजार के कर्मचारियों की 16 दिन हड़ताल के पश्चात 250 कर्मचारियों को स्थायी कराने में सफलता मिली है।

एंग्लोफ्रेन्च ड्रग कम्पनी, बंगलौर में समझौते के फलस्वरूप वेतन में प्रति कर्मचारी 75 रुपये प्रतिमास की बढ़ोत्तरी होकर न्यूनतम वेतन 550 रुपये कराने में सफलता मिली है।

कुद्रेमुख की एच० एस० सी० एल० इम्पलाइज यूनियन ने मजदूरों के वेतन में प्रति मास 150 रुपये से लेकर 200 रुपये की बढ़ोत्तरी करायी है।

कन्सोलिडेटेड कॉफी लि० मंगलोर के कर्मचारियों को समझौते से 20 प्रतिशत बोनस दिलवाया। कॉफी क्यूरिंग कारखानों के ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को बोनस और छुट्टियों की तनखाह दिलवायी।

स्मिथ क्लैन एण्ड फ्रेंच, बंगलोर के कर्मचारियों ने 20 दिन हड़ताल के परिणामस्वरूप डिसमिस किए गये 3 कर्मचारियों को न्यायालय के निर्णय होने तक आधा तनखाह मिल रही है।

बंगलोर के एन० जी० ई० एफ० और शिमोगा के तुंग भद्रा शुगर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल व धरने दिये।

मदुराई के बुनकरों ने आन्दोलन करके बोनस प्राप्त किया।

आई० सी० एफ० तथा दक्षिणी रेलवे की अपनी यूनियनों के प्रयत्न के कारण वहां के कर्मचारियों के लिए मृतक मुआवजा योजना लागू हुयी।

विशाखापटनम के 'नेवल ड्राई डाक' के हजार से अधिक कन्ट्रैक्ट मजदूरों को नियमित कराने में सफलता मिली है।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स को भारत सरकार ने पहली ही बार इस समय वार्ता में सम्मिलित किया है।

मांग सप्ताह

दिनांक 11 अगस्त, 1977 से 28 अगस्त, 1978 तक समूचे देश में बोनस अध्यादेश को वापस लेने, मूल्य वृद्धि को रोकने, आपातस्थिति के उत्पीड़न समाप्त करने तथा निष्कासित कर्मचारियों को काम पर वापस लेने की मांग लेकर मांग सप्ताह मनाया गया।

अभ्यास वर्ग

केन्द्रीय कार्यसमिति के सदस्यों, सभी प्रदेश मजदूर संघ व औद्योगिक महासंघों के अध्यक्षों एवं पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं आदि का सम्मिलित शिक्षण वर्ग दिनांक 14 दिसम्बर से 16 दिसम्बर तक बड़ौदा में सम्पन्न हुआ, जिसमें समूचे देश से कुल 233 प्रतिनिधि सम्मिलित हुये ।

दुर्गापुर (बंगाल) में बर्दवान जिले का एक दिन का प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न हुआ । जिसमें कुल 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

कोटा (राजस्थान) के अभ्यास वर्ग में 225 प्रतिनिधि सम्मिलित हुये, जो 26 व 27 नवम्बर, 1977 को सम्पन्न हुआ ।

आंध्र के तूफान पीड़ितों को सहायता

समुचे देश से भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्धित यूनियनो ने अब तक कुल 30, 500 रुपये की धनराशि आन्ध्र के तूफान पीड़ितों के लिये भेजी है । वहां की अपनी यूनियनों ने पुनर्वास दिलाने के कार्य में भी सक्रिय भाग लिया ।

निर्वाचनों में सफलतायें

गुप्त मतदान के आधार पर निर्मित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० (58 हजार कर्मचारियों के लिये) के ज्वाइन्ट कमेटी में मतों के आधार पर भारतीय मजदूर संघ के 6 प्रतिनिधि लिये गये हैं, जबकि इनटुक के सात, सीटू के 3, आइटक के 4 तथा हिन्द मजदूर सभा के 1 प्रतिनिधि हैं ।

राजस्थान जलदाय योजना में 54 प्रतिशत मत प्राप्त कर प्रथम स्थान ग्रहण किया है ।

चण्डीगढ़ गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग प्रेस में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा 61 प्रतिशत से अधिक मत मिले हैं ।

मेटल वर्क्स, जयपुर तथा यू० पी० इन्डस्ट्रियल लि० लखनऊ में क्रमशः 51 प्रतिशत तथा 94 प्रतिशत मत प्राप्त कर प्रथम स्थान मिले हैं ।

आर्डिनेन्स फैक्टरी (किला) इलाहाबाद के वर्क्स केमेटी के चुनाव में

10 स्थान में 7 स्थान जीते हैं।

विदर्भ के भद्रावती में इन्टुक एवं आयटक के संयुक्त मोर्चे को हराते हुये वर्क्स कमेटी में अपनी यूनियन के 9 प्रतिनिधि चुने गये। नागपुर आर्डिनेन्स फैक्टरी में भी 2 प्रतिनिधि विजयी हुये।

नागपुर रिजर्व बैंक के रिक्रियेशन क्लब तथा सहकारी कैन्टीन में अपने ही समूचे प्रतिनिधि निर्वाचित हुये हैं, साथ ही क्रेडिट सोसाइटी में भी प्रतिनिधि चुनें गये हैं।

इन्टक तथा अन्य संगठनों के संयुक्त मोर्चे के बावजूद नागपुर परिवहन के क्रेडिट सोसाइटी में शत प्रतिशत अपने ही प्रतिनिधि चुने गये हैं।

मीटर इन्स्ट्रमेन्ट्स कारखाना चण्डीगढ़ में भारतीय मजदूर संघ का पूरा पैनेल जीतकर आया, फलस्वरुप ए० आई० टी० यू० सी० से सम्बन्ध विच्छेद कर यूनियन ने भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्धता ग्रहण की है।

वेहिकल फैक्ट्री जबलपुर में वर्क्स कमेटी के चुनाव में हमें 4 स्थान प्राप्त हुये हैं तथा इनटुक व ए० आ० टी० यू० सी० को एक भी स्थान नहीं मिला।

बंगलोर के भारत इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी के सहकारी केन्टीन के चुनाव में भा० म० संघ और एक स्वतन्त्र संगठन ने मिलकर सब सीटें जीती जबकि मान्यता प्राप्त ए० आ० टी० यू० सी० को एक भी स्थान नहीं मिला।

बैठकें और अधिवेशन

अमृतसर अधिवेशन के पश्चात् सम्पन्न हुये कार्यसमिति बैठकें, अधिवेशन तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूची परिशिष्ट 4, 5, 6, 7, 8 व 9 पर दी जा रही है।

अपने कार्य के अलावा अन्य संगठनों द्वारा उठाये गये आन्दोलनों व मांगों का समर्थन

महाराष्ट्र राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन को भारतीय मजदूर संघ ने

समर्थन दिया। इस आन्दोलन को चलाने वाली 2 संस्थाओं में से एक संस्था भारतीय मजदूर संघ की सहयोगी संस्था है।

पंजाब राज्य कर्मचारियों के सांकेतिक हड़ताल का भारतीय मजदूर संघ ने समर्थन दिया।

राष्ट्रीय समस्याओं पर सहयोग

दि० 6 अगस्त, 77 को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय श्रम संस्थाओं तथा औद्योगिक महासंघों की बैठक में भारतीय मजदूर संघ सम्मिलित हुआ।

विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित 18 सितम्बर 77 के ट्रेड यूनियन कन्वेन्शन में भारतीय मजदूर संघ के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दि० 30 व 31 अक्तूबर 77 को भोपाल में "बदले हुए परिवेश में औद्योगिक सम्बन्ध" गोष्ठी में भारतीय मजदूर संघ की ओर से मा० दत्तोपन्त ठेंगड़ी सम्मिलित हुये।

हैदराबाद में आयोजित दि० 23 व 24 दिसम्बर, 77 को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ ने भाग लिया।

दिसम्बर 17 मार्च, 78 को नागपुर में आयोजित "सेमिनार आन इनकम, वेजेज, प्राइजेस पालिसी" में मा० दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने भाग लिया इस सेमिनार का आयोजन आल इन्डिया पोस्टल एकाउन्ट्स इम्पलाइज एसोसियेशन ने किया था।

जनता सरकार ने वादा पूरी की, किन्तु आशा भंग कर दी

30 वर्षों के कांग्रेस के एक छत्र शासन को समाप्त करके पिछले लोक सभा चुनाव में जनता शासन के आने के पश्चात् मजदूरों में आशा व

आकांक्षायें बढ़ी हैं क्योंकि इस परिवर्तन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यद्यपि जनता सरकार ने मजदूरों के हित में बहुत कुछ किया है, तो भी उनकी आशा और आकांक्षाओं की तुलना में यह बहुत कम है। मजदूरों के हितों के लिए सरकार ने जो काम किये हैं, वे निम्नलिखित हैं

(1) श्रमिकों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को पुनर्स्थापित किया।

(2) मई, 74 के अभूतपूर्व रेल हड़ताल में निष्कासित किये गये हजारों मजदूरों को 3 सप्ताह के अन्दर काम पर वापस ले लिया, साथ ही हड़ताल के दिनों को अवकाश के साथ समायोजन करके मजदूरों को पैसे का नुकसान नहीं होने दिया।

(3) आपातस्थिति में निकाले गये कर्मचारियों को काम पर वापस लिया तथा उतने दिनों का वेतन दिलाया।

(4) अनिवार्य बचत योजना समाप्त की।

(5) बोनस कानून को फिर से लागू किया।

(6) कांग्रेस सरकार की भेदभाव व पक्षपात की नीति तथा संगठन विशेष को बढ़ावा देने के रवैय्ये का परित्याग करके निष्पक्ष रुप से सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों को स्थान दिया।

(7) कई वर्षों से न लिये गये त्रिदलीय सम्मेलन को प्रारम्भ करके सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों को समान स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया।

(8) त्रिदलीय सम्मेलन में हुए निर्णय के अनुसार 'समग्र औद्योगिक कानून बनाने के लिये; 'सही निर्देशांक निकालने की पद्धति निश्चित करने के लिये; 'मजदूरों की साझेदारी' तथा 'खेतिहर मजदूरों व अन्य ग्रामीण असंगठित व असुरक्षित मजदूरों की समस्याओं पर' विचार विमर्श करने हेतु सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया।

(9) आकाशवाणी और टेलीविजन द्वारा एक ही संगठन को बढ़ावा देने वाला दुरुपयोग समाप्त हुआ।

(10) यूनियनों की मान्यता निश्चित करने वाली पुरानी गलत पद्धति

को बदलकर अनुपातिक आधार पर संयुक्त सामुहिक सौदेबाजी का सिद्धान्त अपनाया।

(11) बड़े नोटों का विमुद्रीकरण करके आंशिक ही क्यों न हो कालेधन से जनता को बचाया।

(12) बीड़ी मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया तथा कन्ट्रैक्ट और कैजुअल लेबर को नियमित करने की दिशा में विचार प्रारम्भ किया साथ ही बुनकर मजदूरों को संरक्षण दिलाने के बारे में भी कदम उठाने का निर्णय किया।

(13) वर्किंग जर्नलिस्ट को अन्तरिम राहत देने के बारे में प्रशंसनीय निर्णय लिया। यद्यपि प्रेस के मालिकों ने न्यायलय से स्टे लेकर उक्त सुविधा से वंचित करने का निन्दनीय कार्य किया है, साथ ही उन्होंने वेज बोर्ड से भी अपना प्रतिनिधि वापस बुलाकर इस समस्या को और भी जटिल बनाने का प्रयास किया है।

यद्यपि उपर्निदिष्ट मजदूर हितों के अनेक कार्य सरकार ने सम्पन्न किये हैं, तो भी उसके नीति निर्धारण में अनिश्चितता और देरी के कारण मजदूरों में निराशा उत्पन्न हुयी है, साथ ही अनेक कार्य मजदूरों के विरोध में भी किये गये हैं। उस संदर्भ में कुछ उदाहरण यहां दिये जा रहे हैं :

(1) यद्यपि यह बात सही है कि बोनस और अनिवार्य बचत योजना के विषय में अन्ततोगत्वा उचित निर्णय हुआ, लेकिन निर्णय लेने में जो अक्षम्य विलम्ब हुआ वह संदेह से परे नहीं है।

(2) बोनस को 'विलम्बित वेतन' के रुप में स्वीकार करने के बाद भी सरकार ने हरेक वेतन भोगी को बोनस पाने का हकदार बनाने से इनकार कर दिया।

(3) बोनस का अधिकार जो दिया गया, मात्र एक वर्ष के लिए। आगे की नीति अभी तक अनिश्चित है।

(4) सम्बन्धित मंत्री की घोषणा के बावजूद डाक एवं तार के विकिटमाइज कर्मचारियों को राहत नहीं दी गयी।

(5) आपात-स्थिति में बीमा कर्मचारियों के साथ हुये 15 प्रतिशत बोनस के समझौते को रद्द किया गया। उस को इस सरकार ने स्वयं आगे आकर वापस नहीं लिया वरन कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायलय का आश्रय लेकर अपना बोनस वापस लेना पड़ा।

(6) सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्त देने में अनुचित देरी की गयी, साथ ही जो भुगतान किया गया, वह भी नगद में नहीं दिया गया।

(7) चीनी उद्योग के वेजबोर्ड का समय बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, फिर भी उसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया।

(8) सार्वजनिक उद्योग में पुराने वेतन समझौतों की अवधि समाप्त होने के बावजूद 'भूर्तलिगम् समिति' की रिपोर्ट आने का बहाना लेकर वेतन विषयक सभी मामलों को लम्बी देर तक टालने की योजना की गयी।

भारतीय मजदूर संघ और सरकार

भारतीय मजदूर संघ प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। इसलिए किसी प्रकार के राजनैतिक बने बिना भी जनता पार्टी के यशस्विता के लिए इच्छुक है। क्योंकि यदि यह असफल होती है तो जनता न केवल जनता सरकार से वरन अपने देश में जनतंत्र पर से ही आस्था खो बैठेगी। तो भी भारतीय मजदूर संघ का इस नयी सरकार के साथ उसी प्रकार का सम्बन्ध रहेगा, जैसा कि किसी राष्ट्रीय सरकार के साथ किसी एक आदर्श व सही (जेन्यूइन) श्रमिक संगठन का रहना चाहिये।

इस सरकार के साथ ही नहीं वरन् किसी भी सरकार के साथ जो समुचित रुप से निर्वाचित होकर बनी है, ऐसे सभी स्वदेशी व जनतन्त्रीय सरकार के साथ भारतीय मजदूरसंघ का व्यवहार "प्रतियोगीता सहकारिता" रहेगा।

राष्ट्रीय नीति

भारतीय मजदूर संघ ने समय-समय पर देश की समस्याओं पर अपने

विचार प्रकट किये हैं। आज भी कितनी ही समस्यायें हैं, जिनके बारे में पुनः उल्लेख करना ठीक रहेगा।

अनाज तथा कपड़ा, खाने के तेल, चीनी, मछली, मिट्टी के तेल, ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की जाय, जिसका निरीक्षण जन समितियां करें, ताकि इन वस्तुओं की निरन्तर सप्लाई बनी रहे (कम से कम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आधा किला अनाज मिल सके) और यह अच्छे किस्म की हो तथा सस्ते दाम पर रहें।

उद्योगों में स्थापित वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जाय और उत्पादन बढ़ाने में आने वाली रुकावटें दूर की जांय। जिन प्रतिष्ठानों में 50 से कम कर्मचारी है, उन प्रतिष्ठानों में भी जहां बिजली की कटोती अथवा बिजली की कमी से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, उन सभी कर्मचारियों को पूरा मुआवजा दिया जाय।

विभिन्न उद्योगों में आकस्मिक, अस्थायी, बकचार्ज तथा बदली कर्मचारियों को समुचित रुप से नियमित किया जाय।

असुरक्षित व असंगठित मजदूरों के लिऐ प्रत्येक राज्य में कानून बनाये जांय।

भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा ही 'काम के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रुप में जोड़ने के लिये कहा है।

'उद्योगों के श्रमिकीकरण' की मांग का सिद्धान्त भारतीय मजदूर संघ की देन है। हमने औद्योगिक मिलिकयत के आधार पर एक राष्ट्रीय आयोग के निर्माण के लिये मांग की है।

राष्ट्रीय योजना को प्रभावी बनाने की दृष्टि से मजदूरों को योजना के सभी स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया जाय।

यद्यपि वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय आय, मूल्य व वेतन नीति निर्धारित करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की है। किन्तु हमारी मांग है कि राष्ट्रीय आय, मूल्य, उत्पादन और रोजगार नीति को निर्धारित करने के लिये गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाय, जिसमें सभी आर्थिक हितपक्षों का

प्रतिनिधित्व रहे। बिना इस प्रकार के सार्वजनिक विचार मंथन के कोई भी नीति समुचित रुप से कारगर नहीं हो सकती।

वर्तमान सरकार ने स्वयं अपनी औद्योगिक नीति निश्चित की है, उस संदर्भ में हमारा कहना है कि देश के औद्योगिक स्वरुप के अनुकूल उसका प्रारुप तैय्यार होना चाहिये तथा विशेषज्ञ समिति के सुझाव के अनुसार उद्योग के स्थान, आकार व तकनीकी आदि के बारे में आखिरी निर्णय लिये जाय।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, प्राविडेन्ट फण्ड तथा वर्कर्स एजूकेशन आदि की व्यवस्था को सरल बनाया जाय तथा इन्हें मजदूर प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपा जाय।

आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के स्तर पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारण हो। वास्तविक वेतन का पूरा संरक्षण किया जाय। जब तक वर्तमान वेतन और वास्तविक वेतन में अन्तर है, तब तक बोनस को अतिरिक्त (विलम्बित) वेतन माना जाय तथा सभी वेतन भोगियों को बोनस दिया जाय। सूचकांक को वैज्ञानिक आधार पर फिर से निर्धारित किया जाय।

'सार्वजनिक प्रशासन' को विशेष व्यवसाय बनाकर उसे कानूनी मान्यता दी जाय तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्वायत्तता तथा उसके उत्तरदायित्व में सन्तुलन बनाए रखा जाय।

ग्रामीण पिछड़ा और असंगठित क्षेत्र

ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जाय। भूमि सुधारों के कानून को तथा सभी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन मजदूरों में फिर से बांटने की व्यवस्था को लागू किया जाय। उसे विशेषकर उन मजदूरों में बाटा जाय जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर समुचित न्यूनतम वेतन कानून बनाया जाय तथा उसे सभी खेतिहर मजदूरों तथा देश के असंगठित व असुरक्षित क्षेत्र के मजदूरों पर भी लागू किया जाय।

व्यापक रूप से सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों, छोटी सिचाई और मजदूरों को अधिकाधिक संख्या में लगाने वाली योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाय।

बन पर आधारित उद्योगों को संगठित दिया जाय, बनवासी कर्मचारियों को ठेकेदारों और संरक्षकों के षडयंत्रों से बचाया जाय।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिये अपना धन्धा स्वयं प्रारम्भ करने के लिए मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि इन्जीनियरी, डेयरी, कताई-बुनाई और बढ़ईगिरी के माध्यम से सुविधायें दी जांय। पुरातन समय से चले आये व्यवसायों को आज की दृष्टि से उपकरण उपलब्ध कराकर रोजगार देने के उपाय ढूढ़ें जांय। हाथकरघा के बुनकरों को सस्ते मूल्य पर धागे की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित की जाय। लघु उद्योग शुरू करने के लिये शिक्षित बेरोजगारों को राजकीय सहायता दी जाय।

ग्रामीण क्षेत्र में साधन एकत्रित करने की दृष्टि से सामुहिक बैंकिंग एजेन्सी के द्वारा सूक्ष्म नियोजन व्यवस्था लागू की जाय।

पूर्ण रोजगार

पूर्ण रूप से बेरोजगारी समाप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि औद्योगीकरण की नीति को समुचित रूप से मोड़कर अधिक से अधिक लोगों को काम देने के उपाय व धन्धे ढूंढ़ें जांय। उस दृष्टि से बड़े उद्योगों से सम्बन्धित पूरक उद्योग तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जांय। कहीं पर भी जहां मनुष्य के हाथ काम करने में समर्थ हों, स्वचालितीकरण को निरस्त कर दिया जाय।

आर्थिक और वित्तीय अनुशासन

कर ढांचे को संशोधित कर उसे और सुगम बनाया जाय। अप्रत्यक्ष करों की मात्रा न्यूनतम की जाय। आयकर की छूट की सीमा बढ़ाकर 12 हजार कर दी जाय।

विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

विदेशी स्वामीत्व वाले सभी उद्योगों का भारतीय करण तथा लोकतंत्रीकरण किया जाय। विदेशी सहयोग के सभी समझौतों में बन्धनकारी शर्तों को अस्वीकार कर दिये जांय। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में से विदेशी पूंजी को हटाया जाय।

घाटे की अर्थव्यवथा समाप्त की जाय। सभी अशिष्ट बेकार तथा विलासिता के निजी खर्चों पर उपभोक्ता कर लगाया जाय। काले धन की बुराइयों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाये जांय।

करों की चोरी करने वालों, काला बाजारियों, मुनाफा खोरों, जमाखोरों, तस्करों, सटोरियों, मिलावट करने वालों तथा अन्य भ्रष्ट और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़े पग उठाये जाय।

आयातित विदेशी सामान की जगह देश में ही सामान तैयार करने के कार्यक्रम को पूरा प्रोत्साहन दिया जाय। छोटी बचतों को बढ़ावा देकर इस राशि को औद्योगिक विकास में लगाया जाय।

एकीकरण की ओर

आपातस्थिति में वह विचार प्रस्तुत हुआ कि सभी राष्ट्रवादी, लोकतांत्रिक श्रम संस्थाओं का एकीकरण होना चाहिए। इस दृष्टी से नवम्बर-दिसम्बर 1976 में भारतीय मजदूर संघ हिंद मजदूर सभा तथा हिंद मजदूर पंचायन के महाराष्ट्र राज्य के कार्यकर्ताओं की तीन बैठकें बम्बई में हुई। आपातस्थिति हटाने के पश्चात इस उपक्रम को आगे बढ़ाने हेतु दिल्ली में उपरिनिर्दिष्ट तीन संस्थाओं के प्रमुखों की एक बैठक दिनांक 10-11 अप्रैल, 1977 को हुई। इस बैठक में नेशनल लेबर अर्गनाजेशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने चार संस्थाओं के कौन्फेडरेशन का सुझाव रखा, और इस तरह के कौन्फेडरेशन में नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन शामिल होने के लिए तैयार है, बताया, साथ ही विलीनीकरण के लिए उसने अस्वीकृति दी। इस बैठक में विलीनीकरण दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति का मूल्यांकन, ट्रेड्यूनियन एकता के उद्देश्य तथा एकीकरण की प्रक्रिया के विषय में सामान्य मार्ग दर्शक सिद्धान्त स्वीकृत किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 20-4-77 को उपर्युक्त तीन संस्थाओं के बम्बई के कार्यकर्त्ताओं ने प्रयोग के रूप में गिरणी

कामगार सभा की स्थापना श्री बगाराम जी तुलपुले के नेतृत्व में की। (इसी प्रयोग को बाद में माझगांव डॉक में भी दोहराया गया।) दिनांक 7-4-77 को दिल्ली में तीनों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन इस कार्य को आगे बढ़ाने के हेतु किया गया जिसमें संयोजक के नाते श्री बाल दंण्डवते (एच० एम० पी०) को नियुक्त किया गया,

इस कार्य की पृष्ठ-भूमि बनाने की दृष्टि से दिनांक 23-4-77 को बम्बई में सभा—पंचायत-संघ के प्रदेश कार्यसमितियों ने सदस्यों की बैठक भा० म० संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनराव गवंडी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना एकीकरण समिति की स्थापना हुई। इस समिति की जून 1977 की बैठक में विवादग्रस्त विषयों का हल निकालने के लिये एक त्रिसदस्यीय उपसमिति बनाई गई।

विवाद के प्रश्न प्रमुख रूप से चार रहे। जिनमें से एक के विषय में अप्रैल 1977 की दिल्ली बैठक में भा० म० संघ की भूमिका अन्य संस्थाओं ने मान ली थी। वह यानी संयुक्त ट्रेड यूनियन संस्था का स्वरूप पूर्ण रूपेण गैर राजनीतिक रहे, वह किसी भी राजनैतिक दल के अंग के रूप में काम न करें। बम्बई की उपरिनिर्दिष्ट उपसमिति के सामने भा० म० संघ ने तीन प्रश्न विचारार्थ रखे।

(1) भारतीय मजदूर संघ 'वर्ग' कल्पना को नहीं मानता। यद्यपि संघर्ष के विषय में उसकी भूमिका अन्य संस्थाओं के समान है। इसलिये 'वर्ग' संघर्ष शब्द को वर्जित किया जाय।

(2) भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक क्षेत्र में राष्ट्रीय श्रम दिवस का सूत्रपात किया है। अन्य संस्था इसको अबतक नहीं मान रही हैं।

(3) संयुक्त संस्था का ध्वज क्या रहे? लाल झण्डा बी० एम० एस० को स्वीकार नहीं है।

विचार विमर्श के पश्चात यह तय हुआ कि :—(1) वर्ग संघर्ष के बजाय अन्याय शोषण के विरोध में संघर्ष, यह शब्द प्रयोग किया जाय; तथा (2) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और राष्ट्रीय श्रम दिवस दोनों को निर्वाचित संयुक्त संस्था अपनाये।

ध्वज के विषय में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

दिनांक 13, 14 अगस्त, 1977 की भा० म० संघ की अ० भा० कार्य समिति ने पूना की बैठक में एकीकरण के प्रयास का स्वागत किया, और कहा कि तीनों संस्थाओं को एक साथ कार्यसमिति या प्रतिनिधि सभा के स्तर पर स्वयं अपने को विसर्जित कर नई संस्था में शामिल होने का प्रस्ताव पारित करना चाहिये।

हिंद मजदूर पंचायत ने भी अपने जयपुर अधिवेशन में बिना शर्त एकीकरण प्रस्ताव पारित किया है।

हिंद मजदूर सभा के एतत् विषयक निर्णय के पश्चात यह प्रक्रिया अधिक तेज होगी, ऐसी आशा है।

तबतक अन्तरिम कार्यकारी व्यवस्था के नाते तीनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों की केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना करना आज की स्थिति में अति आवश्यक है, ऐसा भा० म० संघ का मन है। भा० म० संघ इस समिति में नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन को भी शामिल करना उपयुक्त समझता है।

रचनात्मक कार्य

भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। हमारे प्रतिनिधि ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को "वयस्क शिक्षा योजना" में पूरे रूप से सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस योजना का विस्तृत ब्योरा अभी सरकार क्रमशः प्रस्तुत करेगी। फिर भी अपनी ओर से योजना बनाकर 'साक्षरता प्रसार' के लिये कुछ कदम उठाना आवश्यक है।

उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को दिलचस्पी लेकर भाग लेना चाहिये ताकि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से श्रमिकों को अच्छे व सस्ते सामान व खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

सहकारिता के आधार पर आवास की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी हम योजना बना सकते हैं।

ग्रामों में चिकित्सा सम्बन्धी वैधिकीय आदि उपचार के सम्बन्ध में भी विचार कर सकते हैं।

उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से हम मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावट आदि बुराइयों को रोकने में समर्थ हो सकते हैं। इस दिशा में हमें प्रभावी कदम उठाना चाहिये।

थोड़े से रचनात्मक कार्य के ये उदाहरण हैं। वास्तव में ऐसे क्षेत्र का बहुत बड़ा दायरा है।

समय की पुकार

वर्तमान समय का बढ़ता हुआ कार्य तथा भविष्य में और भी कार्य बढ़ने की जो आशा है, उसके कारण अपने संगठन को पूर्ण रूप से सक्षम एवं सारे उपकरणों से सम्पन्न रखने की भारी जिम्मेवारी अपने ऊपर है। सभी स्तरों पर अच्छे प्रसंगावधानी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की तथा उन्हें योग्य प्रशिक्षण देने की भी जरुरत है। इसके लिये शिक्षण वर्गों को अधिक कार्यक्षम तथा उपयोगी बनाना होगा।

आज के संदर्भ में केन्द्र व प्रदेशों के कार्यालयों को नई जिम्मेवारी वहन करने की दृष्टि से और भी सक्षम बनाने तथा आर्थिक व इतर दृष्टि से भी समर्थ बनाने की आवश्यकता है।

अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने हेतु क्यों न हो, अपना एक 'पत्र' निकालना पहले से भी अब अधिक आवश्यक हो गया है।

आपातस्थिति के पश्चात् यद्यपि भारतीय मजदूर संघ ने अपने वर्तमान यूनियनों को शक्तिशाली बनाया है, तो भी खेतिहर मजदूर बुनकर तथा बीड़ी मजदूरों तथा इ० डी० स्टाफ (पोस्टल) की ओर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही डाकतार व बैंक अधिकारी तथा सहयोगी संस्था के नाते केन्द्र व राज्य सरकारी कर्मचारी जैसे नये क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है।

निकट भविष्य में भारतीय मजदूर संघ के कार्य व व्यवहार के बारे में भारत का मजदूर और भी आशा रखेगा। यद्यपि यह सत्य है कि अब तक

बहुत कुछ किया गया है, फिर भी बहुत कुछ करना शेष है।

भारतीय मजदूर संघ ने श्रम आन्दोलन को 'राष्ट्र निर्माण' के एक साधन के रुप में माना है। देश भक्त होने के नाते हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि राष्ट्र खड़ा है तो मजदूर गिर नहीं सकता, उसी प्रकार यदि मजदूर खड़ा है तो वह राष्ट्र को कदापि गिरने नहीं देगा। अगर मजदूर गिर जाता है तो राष्ट्र को कोई दूसरी शक्ति बचा नहीं सकती। मजदूर राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र के पुनर्निमाण के कार्य में मजदूर के कन्धों पर भारी जिम्मेवारी है। स्वातंत्र्योत्तर 30 वर्षों में यथा स्थिति तथा अप्रगति ही रही है। विगत 13 मास से ही राष्ट्र की प्रगति प्रारम्भ हुयी है। संगठित मजदूर वर्ग ही इस पुनरुत्थान के कार्य को आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए मजदूरों को भारतीय मजदूर संघ के झंडे के नीचे लाकर उन्हें सक्षम व शक्तिशाली बनाना होगा।

अत: श्रमिक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माणकर्ता के नाते इस 'सर्वोच्च कार्य' को करने के लिए हम कटिबद्ध हो जाय। समय की यही पुकार है।

रामनरेश सिंह
महामन्त्री
भारतीय मजदूर संघ

परिशिष्ट-1

वर्ष 1977 तक भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियन तथा सदस्य संख्या

प्रदेश	यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
1. जम्मू कश्मीर	7	1,500
2. पंजाब	142	90,000
3. चण्डीगढ़	20	4,430
4. हिमाचल	18	10,000
5. हरियाना	62	42,000
6. दिल्ली	76	1,07,230
7. राजस्थान	205	1,90,000
8. उत्तर प्रदेश	292	1,4 ,000
9. बिहार	66	90,325
10. बंगाल	116	38,109
11. आसाम	10	45,252
12. उड़ीसा	11	3 000
13. मध्य प्रदेश	144	75,000
14. गुजरात	28	15,500
15. विदर्भ	45	13,043
16. महाराष्ट्र	123	1,13,074
17. आन्ध्र	75	47,000
18. कर्नाटक	63	26,000
19 तामिलनाडु	2	26,500
20. केरल	50	5,525
योग	1,555	10,83,488

परिशिष्ट-2

वर्ष 1977 तक भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध अ० भा० औद्योगिक महासंघों की यूनियनें तथा सदस्य संख्या

औद्योगिक महासंघ	यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
1. अ० भा० विद्युत मजदूर संघ	—	60,000
2. अ० भारतीय इन्जीनियरिंग मजदूर संघ	—	20,000
3. अ० भारतीय इस्पात मजदूर संघ	8	10,000
4. भारतीय जूट मजदूर संघ	30	26,000
5. भारतीय खदान मजदूर संघ	16	75,000
6. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ	41	19,858
7. भारतीय परिवहन मजदूर संघ	—	34,000
8. भारतीय रेलवे मजदूर संघ	12	3,00,000
9. भारतीय सुगर मिल मजदूर संघ	42	16,000
10. भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ	—	65,000
11. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स	—	70,000
12. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्स्योरेशन वर्कस	28	10,000

13. अ० भा० स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ	100	10,000
14. अ० भा० गैर शिक्षक कर्मचारी संघ	—	3,000
15. अ० भारतीय सीमेन्ट मजदूर संघ	9	16,000
16. अ० भा० खेतिहर मजदूर महासंघ	14	18,000
17. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स	—	19,000

परिशिष्ट-3

त्रिदलीय सम्मेलनों, सलाहकार समितियों, तथा गोष्ठियों आदि में भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व

समिति का नाम	दिनांक	प्रतिनिधित्व करने वाले का नाम
1. आई० एल० ओ० 63 वां अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा	1 जून से 22 जून, 1977	1. श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी
2. त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (दिल्ली)	6 व 7 मई, 1977	1. श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी 2. श्री नरेशचन्द्र गांगुली 3. श्री रामनरेशसिंह 4. श्री बालकृष्ण नरहरि साठ्ये
3. इस्पात मंत्री के साथ नीति विषयक विचार विमर्श	12 अप्रैल, 1977	1. श्री रामनरेशसिंह
4. इस्पात सम्बन्धी अध्ययन समितियां		1. श्री रामनरेशसिंह 2. श्री रामजीदास शर्मा 3. श्री सरोजकुमार मित्र 4. श्री रामदेव प्रसाद 5. श्री श्यम्बकराव जुमड़े 6. श्री आलमपल्ली वेंकटराम
5. वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री के साथ मूल्यों के नियंत्रण के सम्बन्ध में विचार विमर्श		□ श्री हरिकृष्ण पाठक

6. मूल्य सूचकांक संबंधी समिति		☐ श्री बालकृष्ण नरहरि साठ्ये
7. सामाजिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय विकास संबंधी गोष्ठी	19 से 30 सितम्बर, 1977	☐ श्री प्रभाकर घाटे
8. श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार व राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार सम्बन्धी समिति (बम्बई)	29 अगस्त, 1977	☐ श्री ओमप्रकाश अग्गी
9. समग्र औद्योगिक संबंध विषयक विधेयक		☐ श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी/ श्री रामनरेशसिंह
10. ग्रामीण विकास में मजदूर संगठन व मजदूर शिक्षण के योगदान विषयक योजना		☐ श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी
11. ग्रामीण विकास में म० सं० व म० शि० सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी (उदयपुर)	13 से 16 अक्तूबर, 1977	1. श्री नरेशचन्द्र गांगुली 2. श्री प्रभाकर घाटे
12. खान सुरक्षा संबंधी समिति		☐ श्री त्र्यम्बकराव जुमड़े
13. मजदूरों की साझेदारी विषयक समिति		☐ श्री नरेशचन्द्र गांगुली
14. पत्रकारिता क्षेत्र में ट्रेड यूनियन विषयक प्रशिक्षण वर्ग (बम्बई)	12 से 17 सितम्बर, 1977	1. श्री जे० रघुनाथ भट्ट 2. श्री अजय दत्त
15. ट्रेड यूनियन के नेतृत्व सम्बन्धी प्रशिक्षण वर्ग (बम्बई)	26 से 31 दिसम्बर, 1977	1. श्री मदनलाल सेनी 2. श्री भूपेन्द्रसिंह

16. कोयला खदान प्राविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी बोर्ड आफ ट्रस्टी		□ श्री बनारसीसिंह आजाद
17. समुद्र पार ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं का औद्योगिक सम्बन्ध विषयक शिक्षण वर्ग (कोलम्बो योजना के अन्तर्गत) लन्दन यू० कि०	जनवरी से अप्रैल, 1978	□ श्री ए० वेंकटराम
	अप्रैल से जुलाई, 1978	□ श्री रामकुमार
18. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की एपेक्श कमेटी		1. श्री ओमप्रकाश अग्गी 2. श्री टी० एस० रामाराव
19. ग्रामीण असंगठित मजदूर विषयक विशेष सम्मेलन	25 जनवरी, 1978	1. श्री एम० जी० डोंगरे 2. श्री रामप्रकाश मिश्र
20. शिकायत समाधान, स्थायी-आदेशों व घरेलू जांच सम्बन्धी विधियों पर शिक्षण वर्ग (बम्बई)	13 से 18 फरवरी, 1978	1. श्री वीरेन्द्र भटनागर 2. श्री दुर्गापद मुखर्जी 3. श्री बलदेवसिंह 4. श्री ओंकार प्रसाद गुप्त 5. श्री अनन्तराव करम वेड़कर
21. शिक्षा मंत्री के साथ वयस्क शिक्षण पर ट्रेड यूनियनों के दायित्व पर विचार विमर्श	14 फरवरी, 1978	1. श्री नरेशचन्द्र गांगुली 2. श्री प्रभाकर घाटे
22. संगठित क्षेत्र में परिवार कल्याण योजना विषयक राष्ट्रीय गोष्ठी	21 से 24 फरवरी, 1978	1. श्री राजकृष्ण भक्त

23. उद्योग मंत्री के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श	3 मार्च, 1978	1. श्री नरेशचन्द्र गांगुली 2. श्री एच० एन० विश्वास 3. श्री महिनारायण झा 4. श्री ब्रह्मसागर डोगरा
24. एसियाई ग्रामीण संगठनों के ट्रेड यूनियन प्रशिक्षकों का शिक्षण वर्ग तूरीन, इटली	24 अप्रैल, 1978 से 14 जुलाई, 1978	□ श्री एस० जी० डोंगरे

परिशिष्ट 4

केन्द्रीय कार्यसमिति तथा क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठकें

दिल्ली	दिनांक 29 व 30 जून, 1975
बम्बई	दिनांक 15 अक्टूबर, 1975
बम्बई	दिनांक 22 फरवरी, 1976
कलकत्ता	दिनांक 18 अप्रैल, 1976
कानपुर	दिनांक 10 अक्टूबर, 1976
बम्बई	दिनांक 25 व 26 दिसम्बर, 1976
बम्बई	दिनांक 10 फरवरी, 1977
बम्बई	दिनांक 4 व 5 अप्रैल, 1977
पूना	दिनांक 13 व 14 अगस्त, 1977
दिल्ली	दिनांक 18 व 19 सितम्बर, 1977
बड़ोदा	दिनांक 13 व 17 दिसम्बर, 1977
नागपुर	दिनांक 6 व 7 मार्च, 1978
दिल्ली	दिनांक 1 से 7 अप्रैल, 1978

परिशिष्ट 5

प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन

प्रदेश	दिनांक	स्थान	प्रतिनिधि संख्या
1. केरल	4 सितम्बर, 77	त्रिचूर	80
2. हिमाचल	16 व 17 अक्टूबर, 77	मंडी	225
3. पंजाब	19 व 20 नवम्बर, 77	लुधियाना	550
4. उड़ीसा	9 दिसम्बर, 77	राउरकेला	112
5. उत्तर प्रदेश	8 व 9 जनवरी, 78	गाजियाबाद	998
6. हरियाणा	14 व 15 जनवरी, 78	फरीदाबाद	325
7. बिहार	5 व 6 फरवरी, 78	हटिया (रांची)	715
8. दिल्ली	18 व 19 फरवरी, 78	दिल्ली	450
9. मध्य प्रदेश	25 व 26 फरवरी, 78	भिलाई	500
10. जम्मू व कश्मीर	23 मार्च, 78	जम्मू	110

परिशिष्ट 6

औद्योगिक महासंघों के अधिवेशन

औ० महासंघ	दिनांक	स्थान	प्रतिनिधि संख्या
1. चाय मजदूर संघ	मई, 77	दुमदुमा	560
2. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स	8 व 9 अक्टूबर, 77	दिल्ली	1100
3. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स	10 अक्टूबर, 77	दिल्ली	82
4. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्स्योरेन्स वर्कर्स	1 व 2 दिसम्बर, 77	हैदराबाद	250
5. अ० भा० इस्पात मजदूर संघ	31 दिसम्बर व 1 जनवरी, 78	टाटानगर	232
6. अ० भा० सुगर मिल मजदूर संघ	10 जनवरी, 78	गाजियाबाद	125
7. अ० भा० जूट मजदूर संघ	26 जनवरी, 78	हुगली	352

परिशिष्ट-7

रेलवे यूनियनों के अधिवेशन

यूनियन	दिनांक	स्थान	प्रतिनिधि संख्या
1. आई० सी० एफ० कार्मिक संघ	10 अप्रैल, 77	मद्रास	422
2. पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ	मई, 77	गोरखपुर	325
3. दक्षिण मध्य रेलवे कार्मिक संघ	सितम्बर, 77	सिकन्दराबाद	600
4. उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन	11 व 12 सितम्बर, 77	मुरादाबाद	315
5. पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद	8 व 9 अक्टूबर, 77	बड़ौदा	350
6. डी० एल० डब्लू० मजदूर संघ	22, जनवरी, 78	वाराणसी	175
7. चितरंजन रेल कारखाना कर्मचारी संघ	5 फरवरी, 78	चितरंजन	215
8. दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ	11 व 12 फरवरी,78	वाल्टेयर	625
9. मध्य रेलवे कर्मचारी संघ	17 व 18 फरवरी 78	सतना	375
10. पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ	19 व 20 फरवरी 78	मुगलसराय	275

परिशिष्ट-8

आपात स्थिति के मध्य सम्पन्न हुए अधिवेशन

मध्य रेलवे कर्मचारी संघ व पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद	संयुक्त अधिवेशन	बम्बई
पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ	अधिवेशन	गोरखपुर
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश	अधिवेशन	आगरा
भारतीय मजदूर संघ, पंजाब	अभ्यास वर्ग	गोविन्दगढ़
भारतीय मजदूर संघ, गुजरात	अधिवेशन	बड़ौदा
महाराष्ट्र बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन	अधिवेशन	बम्बई
दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ	अधिवेशन	रायपुर
भारतीय मजदूर संघ, बंगाल	अधिवेशन	कलकत्ता
भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र	अधिवेशन	नासिक

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कस आर्गनाइजेशन	अधिवेशन	वाराणसी
भारतीय मजदूर संघ, राजस्थान	अधिवेशन	अजमेर
दक्षिणांचल कार्यकर्ता सम्मेलन		हैदराबाद
भारतीय रेलवे मजदूर संघ केन्द्रीय कार्यसमिति		बम्बई
सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय मंच, उ0 प्रदेश	अधिवेशन	इलाहाबाद
अ० भारतीय जूट मजदूर संघ	अधिवेशन	नैहाटी (बंगाल)